मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
मुंबई
वर्षः 8 अंक 321
गुरुवार, 11 जून 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com
हर खबर निष्पक्षता के साथ

ओमान के पास जहाज पर हमलाः 3 भारतीय लापता, 21 को बचाया गया

नई दिल्ली, 10 जून। ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक पोत सेटेबेलो पर हुए हमले को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू ने जेसन मीक्स को बुलाकर इस हमले पर भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ओमान तट के पास हुए हमले में जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि तीन भारतीय अब भी लापता हैं।

भारत ने इससे पहले इस हमले की निंदा करते हुए कहा था कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह क्षेत्रीय संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तत्काल बंद होना चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, "हम ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत 'सेटेबेलो' पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से अब तक 21 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि तीन भारतीयों के लापता होने की सूचना है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह वहां जारी संघर्ष का सीधा परिणाम हैं। बयान में कहा गया, "हम सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ताओं को सफल बनाने की अपील करते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन और व्यापार बहाल किया जाना चाहिए। इससे पहले ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि ओमान तट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की सूचना मिली है। दूतावास ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पश्चिम एशिया में दोबारा बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि 100 दिनों से अधिक समय से जारी संघर्ष ने भारी मानवीय संकट पैदा किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर असर डाला है। मंत्रालय ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की थी। इससे पहले सोमवार को भी पालाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी मैरिवेक्स में आग लगने की घटना के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। यह घटना होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिण में हुई थी।मंगलवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि एमटी मैरिवेक्स ओमान तट के पास निष्क्रिय हो गया था। जहाज पर मौजूद सभी 24 चालक दल के सदस्य भारतीय नागरिक थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने इस बचाव अभियान में सहयोग के लिए ओमान सरकार का आभार भी व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पश्चिम एशिया में दोबारा बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि 100 दिनों से अधिक समय से जारी संघर्ष ने भारी मानवीय संकट पैदा किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर असर डाला है। मंत्रालय ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की थी।

टेस्ट कप्तान शान मसूद और कोच सरफराज खान के भविष्य पर लिया जाएगा फैसला

कराची, 10 जून। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के शीर्ष अधिकारी इस सप्ताह के आखिर में होने वाली बैठक में टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और मुख्य कोच सरफराज अहमद के भविष्य पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। बैठक में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी शामिल होंगे।

इसमें यह तय किया जाएगा कि बांग्लादेश दौरे पर टीम की 0-2 से शर्मनाक हार के बाद शान मसूद और सरफराज खान को आगामी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरों के लिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ बरकरार रखा जाए या नहीं। पीसीबी सूत्र ने कहा कि सबसे अहम फैसला शान मसूद के वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरों पर टेस्ट टीम के कप्तान बने रहने पर होगा। सूत्र ने कहा कि कुछ चयनकताओं और बोर्ड के कुछ अधिकारियों का मानना है कि अब टेस्ट टीम की कप्तानी सलमान अली आगा को सौंपने का समय आ गया है। हालांकि मसूद कप्तानी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश दौरे के निराशाजनक प्रदर्शन का असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है। आगा सीमित ओवरों के प्रारूप में राष्ट्रीय टीम की अगुआई कर चुके हैं। वह फिलहाल टी-20 टीम के कप्तान हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि पीसीबी ने अभी तक सरफराज खान के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं किया है। पूर्व कप्तान यूनिस खान को अगले मुख्य कोच के रूप में गंभीर दावेदार माना जा रहा है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सड़कों पर क्यों बह रहा खून, कौन सी मांगों को कुचलने में जुटी सेना

इस्लामाबाद, 10 जून। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की सड़कों पर खून बह रहा है। पाकिस्तान के केंद्रीय शासन और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने वाले मासूमों को कुचलने के लिए सैन्य आलाकमान ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने तक के आदेश सुना दिए हैं। इसका असर यह हुआ है कि पूरे पीओके में तनाव की स्थिति है। मुजफ्फराबाद में तो सुरक्षाबल-पुलिस की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाए जाने की भी बातें सामने आई हैं, जिनमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा के घायल होने की खबरें हैं। हालांकि, असल आंकड़े क्या हैं, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। इनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि, असल आंकड़ों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। शुरूआत में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ यह विद्रोह रावलकोट तक सीमित था। हालांकि, सुरक्षाबलों की बर्बरता के चलते अब इस प्रदर्शन का फैलाव-मुजफ्फराबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुधनोती, और भीमबर जैसे कई अन्य प्रमुख इलाकों में फैल गया है। पाकिस्तानी प्रशासन ने दमनकारी नीतियां अपनाते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) नाम के संगठन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 100 से ज्यादा जेएएसी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और मुजफ्फराबाद स्थित उनके केंद्रीय कार्यालय पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शनकारी नेताओं पर हत्या जैसे गंभीर आरोपों के पुराने मुकदमों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है। क्षेत्र से जानकारी को बाहर आने से रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 12 जून तक के लिए पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी लोगों और पर्यटकों को 20 जून तक इस क्षेत्र में यात्रा न करने और जो वहां मौजूद हैं उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

बांग्लादेशी लुटेरों का गिरोह पकड़ाः पुलिस से बचने को अंडरपास में कूदे

गुरुग्राम, 10 जून। गुरुग्राम के सेक्टर-23 में सेवानिवृत्त कर्नल के बेटे विकास जैन और उनकी पत्नी व बेटी को बंधक बनाकर लूटने करने वाले चार नकाबपोश बदमाश बांग्लादेश के नागरिक थे। अपराध शाखा पालम विहार की टीम आरोपियों को पकड़ने बजघेड़ा अंडरपास के पास पहुंची। चारों आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगभग 20 फीट नीचे अंडरपास में कूद गए। इस दौरान तीन आरोपियों के पैर तो चौथे के हाथ की हड्डी टूट गई। एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि आरोपियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ कर लूटी गई जूलरी व अन्य सामान बरामद किया जाएगा। पालम विहार थाना इलाके में सेक्टर-23 के सेवानिवृत्त कर्नल सी एल जैन के मकान में ये वारदात 3 जून की देर रात ढाई बजे हुई थी। पीछे की ओर से पहली मंजिल पर पहुंचे चार नकाबपोश बदमाशों ने पहली मंजिल पर रहने वाले कर्नल के बेटे विकास जैन, उनकी पत्नी व बेटी को बंधक बनाया। बदमाश एक कमरे की खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल काटकर अंदर घुसे। यहां लगभग आधे घंटे तक दंपती व बेटी को बंधक बनाकर जूलरी, नकदी व अन्य सामान लूटकर आरोपी धमकी देने के बाद भाग गए। पालम विहार थाना में 4 जून को एफआईआर दर्ज हुई। मामले में थाना पुलिस के साथ ही अपराध शाखा टीमों को भी जांच में लगाया गया। अपराध शाखा पालम विहार की टीम को मंगलवार 9 जून की देर रात सूचना मिली कि लूटपाट करने वाले गिरोह के चार बदमाश बजघेड़ा अंडरपास के पास मौजूद हैं। चारों अब फिर से किसी लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अपराध शाखा टीम यहां पहुंची तो पुलिस को देखकर चारों आरोपी सड़क से नीचे अंडरपास में कूद गए। लेकिन ऊंचाई से कूदने पर नीचे गिरते ही चारों को चोट लगी।

फिर ईरान पर करेंगे बड़ा हमला', डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को चेतावनी, पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव

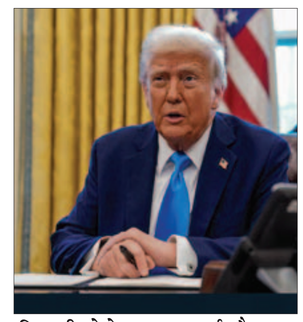

वॉशिंगटन, 10 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने की घटना के बाद अमेरिका ईरान पर बड़े हमले जारी रखेगा। एनबीसी न्यूज से बातचीत में ट्रंप से पूछा गया कि उन्होंने ट्रुथ सोशल पर किए गए अपने पोस्ट में ईरान को इसकी कीमत चुकाने की बात कहकर क्या संकेत दिया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हम उन पर हमला करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में एक बम लगाया गया था, लेकिन वह फटा नहीं। उन्होंने कहा, "हमने कल उन्हें जोरदार तरीके से निशाना बनाया था और आज फिर उन्हें कड़ा जवाब देंगे।" ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी हालिया घटनाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने एक ऐसे सौदे पर बातचीत करने में बहुत लंबा समय लगा दिया जो उनके लिए बहुत अच्छा होता, और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा, "ईरान सिर्फ बातें करता है, कार्रवाई नहीं करता। पश्चिम एशिया का दबंग अब खत्म हो चुका है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर एक अमेरिकी हेलिकॉप्टर गिराए जाने की रिपोर्टों के बाद ईरानी ठिकानों के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए थे। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और गहरा गया।इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी हमले या धमकी को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। उनकी इस कड़ी प्रतिक्रिया ने आगे और अधिक सैन्य वृद्धि की आशंकाओं को जन्म दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया, जब ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दक्षिणी ईरान में अमेरिका के हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी-संबंधित ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।

राम मंदिर दान प्रकरणः संघ ने मांगी रिपोर्ट, बड़े बदलाव के संकेत

अयोध्या , 10 जून। राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन के आरोप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर की व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार, मामले में जांच प्रक्रिया के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। जांच के दायरे में आए कुछ कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने अथवा उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कार्यरत कई कर्मचारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया जा सकता है, ताकि व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाया जा सके। सूत्र बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट पहले से ही मामले की आंतरिक जांच करा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, लेखा अभिलेखों और संबंधित कर्मचारियों की गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा और श्रद्धालुओं के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था में जल्द ही व्यापक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने, निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने तथा वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। वहीं बुधवार को भी तरह-तरह की चचाएं होती रहीं। बुधवार को कथित तौर पर गबन हुई डेढ़ करोड़ की राशि के बरामद होने की बात सामने आई। संदिग्धों से पूछताछ, उनके बैंक डिटेल आदि की जांच का क्रम जारी होने की चर्चा भी जोरों पर रही है। गबन के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। माना जा रहा है कि दान के पैसों की गिनती में लगे बैंक कर्मियों की भी जांच हो रही है। फिलहाल पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट ने चुप्पी साध रखी है। इस बीच, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का हालिया अयोध्या दौरा भी चचाओं के केंद्र में है। 13 जून को निर्माण समिति की बैठक भी होगी। बैठक में शामिल होने के लिए नृपेंद्र मिश्र फिर अयोध्या पहुंचेंगे, माना जा रहा है कि इस बैठक में भी गबन के आरोपों पर चर्चा की जाएगी। इसी माह के अंत में हर तीसरे माह होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक भी संभावित है, जिसमें सभी ट्रस्टियों के जुटने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। राम मंदिर में पूर्व लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह के दावों ने भी पूरे मामले को हवा देने का काम किया है। शल मीडिया पर उनके बयानों का वीडियो वायरल हो रहा है। महिपाल सिंह का दावा है कि राम मंदिर की दान राशि में चोरी लंबे समय से होती आ रही है। नोटों की गड्डियों में हेराफेरी कर पैसे की चोरी की जाती थी। उन्होंने व्यवस्था से जुड़े कुछ वरिष्ठ लोगों के नाम भी लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले पर शिकायत करने पर उन्हें हटा दिया गया था। सरयू तट स्थित करतलिया आश्रम के महंत बालयोगी रामदास ने भी राम मंदिर में चढ़ावे की राशि के गबन से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मालवीय नगर अग्निकांड : एक और घायल विदेशी महिला ने तोड़ा दम

नई दिल्ली, 10 जून। दक्षिण जिले के मालवीय नगर में हौज रानी के फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। बुधवार को एम्स के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन बांग्लादेशी महिला (40) ने अंतिम सांस ली। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने विदेशी महिला की मौत होने की पुष्टि की है। इस अग्निकांड में मरने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या 14 हो गई है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह महिला उन 49 मेहमानों में शामिल थी, जिन्हें 3 जून को दक्षिण दिल्ली के हौज रानी में होटल में लगी भीषण आग के बाद बचाया गया था। बचाए गए लोगों में से 21 को घटना के तुरंत बाद अस्पतालों में मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि एक की मौत रविवार को हो गई थी। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दर्दनाक हादसे में 13 विदेशी नागरिकों और नौ भारतीयों की जान गई है। मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में मैक्स हॉस्पिटल ने एक बयान जारी कर कहा है कि अभी अस्पताल में कुल नौ मरीज भर्ती हैं। इनमें से सात को बृहस्पतिवार को डिस्चार्ज किया जाएगा। फिलहाल, एक मरीज का आईसीयू में इलाज चल रहा है जबकि बाकी आठ मरीज भी भर्ती हैं और सभी की हालत स्थिर है।

मोदी युग के बारह वर्षः विकास, विश्वास और विराट का उदय

-ललित गर्ग

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ कालखंड केवल शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण के लिए याद किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते बारह वर्षों का दौर ऐसा ही एक कालखंड है। यह केवल एक प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जिसने स्वयं को नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई वैश्विक पहचान के साथ स्वयं को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रमाण है जो बार-बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारत जैसा विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश किसी नेतृत्व को लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेश दे, यह अपने आप में असाधारण एवं ऐतिहासिक घटना है। मोदी युग की सबसे बड़ी विशेषता केवल विकास नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का समन्वय है। नेहरू युग को आधुनिक भारत के निर्माण का काल कहा गया, तो मोदी युग को उस भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। मोदी ने केवल सड़कें, पुलों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि भारत किसी से कम नहीं है और वह विश्व मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। मोदी की सबसे विलक्षण विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे जनभावनाओं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ा। वे उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें जनआंदोलन का स्वरूप दिया। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफाई का विषय जो कभी सरकारी विभागों तक सीमित था, उसे राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया।

मोदी युग को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी याद किया जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक बना। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सोमनाथ जैसे तीर्थों का विकास यह संकेत देता है कि आधुनिकता और परंपरा एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती हैं। मोदी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने भारत की विदेश नीति को आत्मविश्वास का नया आयाम दिया। कभी विश्व शक्तियों के बीच संतुलन साधने वाला भारत आज वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संकट हो, जी-20 का नेतृत्व हो अथवा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज उठाने का प्रश्न- भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई है। यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया उसकी ओर समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में देख रही है। इन बारह वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। शासन की पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका सीमित हुई। डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली का एक विशिष्ट पक्ष उनका संकल्पबोध है। वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप देते हैं। चाहे 370 का उन्मूलन हो, तीन तलाक पर रोक हो, जीएसटी लागू करना हो, महिला आरक्षण विधेयक हो अथवा नक्सलवाद और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति-इन सभी निर्णयों में राजनीतिक जोखिम था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाने का साहस दिखाया। यही साहस उन्हें सामान्य राजनेताओं से अलग करता है। हालांकि, किसी भी लोकतांत्रिक शासन की तरह चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ती लागत, सामाजिक विषमताएं तथा आर्थिक अवसरों का असमान वितरण ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान अभी अपेक्षित है। भारत यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ चिकित्सा, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। मोदी सरकार के आगामी वर्षों में सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाए। भारत को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां ईमानदारी अपवाद नहीं, सामान्य व्यवहार बने। शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यावसायिक माफियाओं के प्रभाव से मुक्त कर आम नागरिक की पहुंच में लाना भी समय की मांग है। साथ ही उद्यमिता को बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित रखने के बजाय गांवों, युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाना होगा ताकि प्रत्येक नागरिक रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे अनेक अवसरों पर मिलने और उन्हें निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2007 में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात के आदिवासी अंचल कवांट में पूज्य आदिवासी जैन संत गणि राजेंद्र विजयजी के सान्निध्य में आयोजित एक विराट आदिवासी सम्मेलन में उनसे विस्तृत संवाद का अवसर मिला। उस सम्मेलन में वे केवल औपचारिक अतिथि के रूप में नहीं आए थे, बल्कि अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ उपस्थित होकर आदिवासी समाज के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया था। उसी अवसर पर उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक उत्थान हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को हमारे सुखी परिवार फाउंडेशन को संचालित करने के लिए प्रदान किया तथा आदिवासी विकास की दिशा में ऐतिहासिक 15,000 करोड़ रुपये की वनबंधु कल्याण योजना की घोषणा की। यह उनकी दूरदृष्टि और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच का प्रमाण था। इसी सम्मेलन के दौरान एक अत्यंत रोचक और ऐतिहासिक प्रसंग भी सामने आया। गणि राजेंद्र विजयजी ने नरेंद्र मोदी से कहा-₹आपको दिल्ली जाना चाहिए और देश की बागडोर संभालनी चाहिए₹ तब सहज मोदीजी ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया-मुझे दिल्ली कौन ले जाएगा?₹ किंतु संतों की वाणी में एक विशेष शक्ति होती है। जो बात उस समय एक साधारण संवाद प्रतीत हुई, वही कुछ वर्षों बाद भविष्यवाणी के रूप में सत्य सिद्ध हुई। उन दिनों गुजरात सचिवालय में भी अनेक बार उनसे और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला। वहां जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात थी, वह उनकी कार्यसंस्कृति का प्रभाव था। सचिवालय में बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी भी आत्मानुशासन, समयपालन और स्वावलंबन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते थे। अपने छोटे-छोटे कार्य स्वयं करना, अनावश्यक ताम्झाम से दूर रहना, समय का सदुपयोग करना और जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानना वहां की प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। स्पष्ट महसूस होता था कि यह कार्यशैली शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा से विकसित हुई है। नरेंद्र मोदी केवल आदेश देने वाले प्रशासक नहीं हैं, बल्कि अपने आचरण से व्यवस्था को दिशा देने वाले नेतृत्वकर्ता हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि इस ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया तो भारत केवल विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसी प्रकार महिला शक्ति को विकास की मुख्यधारा में पूर्ण भागीदारी देकर राष्ट्र निर्माण की गति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। मोदी युग की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद आंकड़ों, परियोजनाओं या चुनावी जीतों में नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में है जो भारत के जनमानस में दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी ने बारह वर्षों में विकास की संरचनाएं खड़ी कीं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने करोड़ों भारतीयों के भीतर भविष्य के भारत की एक आकांक्षा जगाई है। 2047 के विकसित भारत का उनका संकल्प तभी साकार होगा जब विकास के साथ विश्वास, समृद्धि के साथ समान अवसर और शक्ति के साथ संवेदनशीलता भी जुड़ेगी। यदि यह संतुलन बना रहता है, तो इतिहास मोदी युग को केवल एक लंबे राजनीतिक कार्यकाल के रूप में नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक उदय के युग के रूप में याद करेगा।

इंडिया गठबंधन की घटती ताकत और बढ़ती उम्मीदे-कितनी सफल होगी

अशोक भाटिया

पाँच जून, 2024 को दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने आखिरी बैठक की थी। इसके ठीक दो साल बाद छह जून को दिल्ली में ही इस प्रमुख विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई है इन दो सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। तब 25 क्षेत्रीय पार्टियों ने बैठक में हिस्सा लिया था। इस बार ये संख्या घटकर 23 रह गई तब पार्टी की बैठक में गैर कांग्रेसी पाँच मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इस बार महज एक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे।अब आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके समेत अन्य कई पार्टियों के लिए राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। हालांकि गठबंधन को मजबूत करने के लिए इंडिया ब्लॉक ने अब हर दो महीने में बैठक करने का फैसला किया है।

इस बैठक में भी एसआईआर के मुद्दे को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। साथ ही, संसद सत्र के दौरान एलओपी राहुल गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक किए जाने का भी फैसला हुआ है।जिन पाँच अहम मुद्दों पर इस विपक्षी गठबंधन में सहमति बनी है, उसमें एक प्रमुख मुद्दा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ा है।

बीजेपी के उभार के बाद देश भर में क्षेत्रीय पार्टियाँ कमजोर हुई हैं। क्षेत्रीय पार्टियों से चुनौती न केवल बीजेपी को मिलती थी बल्कि कांग्रेस को भी मिलती थी। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद घोषित हुए पाँच मुद्दों में सबसे ज्यादा अहम इस बात को माना कि वे हर दो महीने में एक बैठक करेंगे। उनका मानना है कि इससे ही आगे का रास्ता निकलेगा।

इंडिया गठबंधन ने हर दो महीने में बैठक करने का फैसला लिया है। बैठकर बात ही नहीं करेंगे, रणनीति ही नहीं बनाएंगे तो अलायंस का मतलब ही क्या है? फिर तो ये नारा ही है न।"बीते दो साल में ये गठबंधन एक ऑप्टिक्स, एक नारा बनकर रह गया था। अब हर दो महीने में मिलेंगे, भले लड़ेंगे-भिड़ेंगे, जो भी बातें होंगी और जो भी मुद्दे सामने आएंगे, इससे कुछ तो निकलेगा। तो मैं मानती हूँ कि सबसे अहम है।

वैसे इस समय इंडिया ब्लॉक पर बहुत दबाव है। गौर करें कि जब 2023 में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी तब इसके कई नेता सत्ता में थे। खुद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थीं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान, झारखंड में हेमंत सोरेन, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार चला रहे थे। केरल में वामदलों की तरफ से पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। कांग्रेस भी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में अपने बूते की सरकार चला रही थी। ममता बनर्जी की जिद के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उतना एकजुट नहीं रह पाया, जितने की उम्मीद की जा रही थी। आज आलम है कि इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वह सभी सत्ता से बाहर हैं। केवल हेमंत सोरेन झारखंड जैसे छोटे राज्य में सत्ता चला रहे हैं और कांग्रेस की कुछ एक राज्यों में सरकारें हैं।

गौरतलब है कि इस समय सभी दलों को अपना अस्तित्व बचाने की चिंता है ।2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा भाजपा को बहुमत के भीतर रखने में सफल होने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि उनकी स्थिति बेहतर होगी। दरअसल, लोकसभा चुनाव में काफी आत्मविश्वास दिखाने वाली बीजेपी नतीजों में थप्पड़ मारकर होश में आ गई और बाद के सभी विधानसभा चुनाव जीत गए। इसके विपरीत, उन्होंने अधिक जोश के साथ काम किया और विधानसभा की हार भारतीय गठबंधन के लिए एक चेतावनी थी और 'इंडिया सूबेदार' यह समझने में विफल रहे कि उनका पूरी तरह से मोहभंग हो गया था और उनका मानना था कि भाजपा महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में सफल नहीं होगी।भाजपा को 'चरसो पार' का दावा करते हुए जितना भ्रम था, विपक्षी दल विभिन्न विधानसभा चुनावों में सुकून लेकर रहे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए सार्वजनिक रूप से लड़ने वाली शिवसेना-कांग्रेस की बयानबाजी से लेकर पश्चिम बंगाल में खुद को बुद्धिमान मानने वाले भद्रलोकी बाबूमोसाई तक, भाजपा ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। 24 घंटे लगातार राजनीति कर रही भाजपा और चुनाव के लिए बिल से बाहर निकलने वाले विपक्षी नेताओं के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा, इसका जवाब देने के लिए किसी राजनीतिक पंडित की जरूरत नहीं है। इस प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद दो साल में सभी विपक्षी नेताओं की संस्थाएं ध्वस्त कर दी गईं और सभी को एक साथ आना पड़ा। इस बैठक पर ध्यान देने का एक कारण भी यही है। दूसरा कारण यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा, जो अपनी बौद्धिक चपलता और बुद्धिमता खो रही है, विपक्षी दलों के साथ आने का अच्छा समय नहीं है। भाजपा आज राजनीतिक रूप से अजेय लग सकती है, लेकिन यह चुनावी राजनीति तक ही सीमित है। लेकिन आज भाजपा की हकीकत यह है कि पिछले साल कश्मीर हमले के बाद भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस तथ्य के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं कि आज अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा करीब महसूस करता है। लेकिन आज पाकिस्तान अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी चीन के भी करीब है, हमने ताजा युद्ध में ईरान को नुकसान पहुंचाकर अपने एक समर्थक को खो दिया है, आर्थिक मोर्चे पर रुपये का हर दिन अवमूल्यन हो रहा है और बेरोजगार लोगों की बढ़ती संख्या असहाय महसूस कर रही है। न्यायिक या किसी अन्य स्वायत्त प्रणाली के बारे में बात करने के लिए कोई बेहतर स्थिति नहीं है, और अगर सत्तारूढ़ दल का कोई विकल्प नहीं है, तो यह वास्तविकता लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। हवा का पक्ष लें। यह घटना इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि ये विरोधी 'भारत' गठबंधन के मौके पर एक साथ आए हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा अब हार की कगार पर है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपना विवेक पूरी तरह से खो दिया है। लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि यह स्थिति सत्ता में बैठे लोगों की नीतिहीनता को उजागर करने के लिए आदर्श है। ऐसे में विपक्ष यह भूल गया होगा कि शासकों से सवाल करना उनका स्वाभाविक कर्तव्य है। इंडिया अलायंस की बैठक के मौके पर सुधार की सुगबुगाहट देखने को मिली। इसकी जरूरत थी। इसके पूरा होने के बाद अब इस गठबंधन को एक रास्ते पर चलना होगा।

अगर विपक्ष भूल गया है कि यह कैसे करना है, तो उसे 2012 से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। भ्रष्टाचार से लेकर रुपये के अवमूल्यन तक, झुलसते कश्मीर से लेकर झुलसते पूर्वोत्तर तक, हर सवाल का जवाब मोदी ने अकेले ही उस समय ऐसा माहौल बना दिया था। उस समय भी उन्हें अपनी पार्टी का पूरा समर्थन नहीं मिला था। फिर भी, मोदी ने अपने घोड़ों को पकड़ लिया। हालांकि अब कई लोगों को लगता है कि वह उस समय किए गए किसी भी दावे को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय उन पर भरोसा किया गया था। उस समय खुद पर विश्वास पैदा करने में मोदी की सफलता ने लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया।

भारतीय गठबंधन को अब लोगों को यह नहीं बताना चाहिए कि सत्ताधारी कितना गलत है और लोग इसे जानते हैं और महसूस करते हैं। इंडिया अलायंस को सच्चाई से परे जाना चाहिए और मतदाताओं के मन में यह स्थापित करना चाहिए कि उनकी नीतियां सत्ताधारियों की नीतियों का पर्याय हैं। विरोधियों को इस महत्वपूर्ण सत्य को नहीं भूलना चाहिए। विपक्ष को नकारात्मकता और निराशा को दूर करना चाहिए और काम पर लग जाना चाहिए। राम गणेश के 'राजसंन्यास' के जीवाजीपंत कहते हैं, ₹एक भी सिंहगढ़ ऐसा नहीं है जिसके पास द्रणागिरी की धार न हो जिस पर छेद किया जा सके। विरोधियों को इस बढ़त को खोजने के लिए कौशल विकसित करना होगा। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है।

एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र : समय की मांग और लोकतंत्र की जरूरत

-सुरेश गांधी

देश में आज पत्रकारों की संख्या लाखों में है, लेकिन उनकी पहचान के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। परिणाम यह है कि अलग-अलग संस्थानों, संगठनों, पोर्टलों और तथाकथित मीडिया मंचों द्वारा जारी हजारों पहचान पत्रों के बीच वास्तविक और फर्जी पत्रकारों में अंतर करना प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के लिए चुनौती बन गया है। कई राज्यों में पत्रकारिता की आड़ में वसूली, दबाव की राजनीति और प्रभाव के दुरुपयोग के मामले सामने आते रहे हैं, जिससे पूरे मीडिया जगत की साख प्रभावित होती है। विडंबना यह है कि सरकारें पत्रकार कल्याण योजनाएं चलाती हैं, लेकिन लाभार्थियों की प्रमाणिक पहचान सुनिश्चित करने का कोई एकीकृत तंत्र मौजूद नहीं है। जब देश आधार, डिजिलॉकर, आयुष्मान कार्ड और एक राष्ट्र-एक पहचान जैसी व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है, तब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए एक राष्ट्रीय, डिजिटल और प्रमाणित पत्रकार पहचान पत्र क्यों नहीं? अब यह केवल सुविधा का नहीं, बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न बन चुका है, जिस पर सरकार को निर्णायक पहल करनी ही होगी

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की मजबूती चार स्तंभों–विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया–पर टिकी हुई है। इनमें मीडिया को लोकतंत्र का ₹चौथा स्तंभ₹ कहा जाता है क्योंकि यह जनता और सत्ता के बीच संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस पत्रकारिता की पहचान सत्य, विश्वसनीयता और जनसरोकारों से होनी चाहिए, आज उसी क्षेत्र में पहचान का संकट गहराता जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों, जिलों और कस्बों में अनेक संस्थाएं, संगठन, पोर्टल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और मीडिया मंच अपने-अपने स्तर पर पत्रकार पहचान पत्र जारी कर रहे हैं। इनमें से अनेक संस्थाएं प्रतिष्ठित हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मंच भी हैं जो बिना किसी स्पष्ट मानक या वैधानिक प्रक्रिया के पहचान पत्र बांट रहे हैं। परिणामस्वरूप पत्रकारिता की आड़ में फजीर्वाड़ा, दबाव की राजनीति, अवैध वसूली और प्रशासनिक दुरुपयोग जैसी शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे समय में ₹एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र₹ की अवधारणा केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पत्रकारिता की गरिमा और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम बन सकती है।

पहचान का संकट क्यों?

आज यदि किसी जिले में कोई व्यक्ति स्वयं को पत्रकार बताता है, तो उसकी पहचान की पुष्टि करना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसके पास किसी संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र हो सकता है, लेकिन यह तय करना आसान नहीं होता कि वह वास्तव में सक्रिय पत्रकार है या केवल पत्रकारिता के नाम का उपयोग कर रहा है। पुलिस, प्रशासन, सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि किसे वास्तविक पत्रकार माना जाए और किसे नहीं। कई बार घटनास्थलों, वीआईपी कार्यक्रमों, संवेदनशील क्षेत्रों या आपदा स्थलों पर भी इसी कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के विस्तार ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। आज कोई भी व्यक्ति वेबसाइट या यूट्यूब चैनल बनाकर स्वयं को पत्रकार घोषित कर सकता है। डिजिटल पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए अवसर भी है, लेकिन इसके साथ पहचान और जवाबदेही का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

फर्जी पत्रकारिता की बढ़ती चुनौती

देश के अनेक राज्यों में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोगों ने पत्रकार पहचान पत्र का उपयोग कर अधिकारियों पर दबाव बनाने, अवैध वसूली करने, सरकारी दफ्तरों में प्रभाव दिखाने या निजी स्वार्थ साधने का प्रयास किया। ऐसे लोगों की गतिविधियों का सबसे अधिक नुकसान उन हजारों ईमानदार पत्रकारों को उठाना पड़ता है जो कठिन परिस्थितियों में जनहित की खबरें जुटाने का कार्य करते हैं। जब कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में अनुचित गतिविधियां करते हैं, तो पूरे मीडिया समुदाय की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। यही कारण है कि पत्रकारिता से जुड़े अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से एक ऐसी व्यवस्था की मांग करते रहे हैं जिसमें पत्रकार की पहचान स्पष्ट, प्रमाणित और राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो।

क्या हो सकता है ₹एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र₹?

इस व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्यों के समन्वय से एक ऐसा राष्ट्रीय पत्रकार पहचान पत्र जारी किया जा सकता है, जिसे पूरे देश में मान्यता प्राप्त हो। यह पहचान पत्र आधुनिक तकनीक आधारित हो सकता है, जिसमें– यूनिक पहचान संख्या, क्यूआर कोड, डिजिटल सत्यापन प्रणाली, संस्थान का विवरण, कार्यक्षेत्र, वैधता अवधि, और नवीनीकरण की व्यवस्था शामिल हो। किसी भी अधिकारी, संस्था या आम नागरिक द्वारा क्यूआर कोड स्कैन कर पत्रकार की पहचान और संबद्धता की पुष्टि की जा सके। इससे फर्जी पहचान पत्रों की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है।

वास्तविक पत्रकारों को क्या लाभ होगा?

1. पहचान की राष्ट्रीय मान्यता :

आज एक राज्य में जारी पहचान पत्र दूसरे राज्य में कई बार मान्य नहीं माना जाता। राष्ट्रीय पहचान पत्र होने से पत्रकार देश के किसी भी हिस्से में अपनी पहचान आसानी से स्थापित कर सकेगा।

2. सुरक्षा में सुधार : पत्रकार अक्सर दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, चुनावों, अपराध स्थलों और संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनकी पहचान स्पष्ट होना बेहद आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणित पहचान पत्र सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति वास्तव में पत्रकार है।

3. कार्यक्रमों में पारदर्शिता : सरकारी कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधानसभा, संसद, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और वीआईपी कार्यक्रमों में प्रवेश को लेकर कई बार विवाद होते हैं। एक समान पहचान पत्र से मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सकती है।

4. योजनाओं का बेहतर लाभ : केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर पत्रकारों के लिए बीमा, स्वास्थ्य सहायता, पेंशन, दुर्घटना सहायता, आवास और कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती हैं। लेकिन कई बार पात्र पत्रकारों की पहचान और सत्यापन में कठिनाई आती है। यदि एक राष्ट्रीय डाटाबेस उपलब्ध हो तो वास्तविक पत्रकारों तक लाभ पहुंचाना कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगा।

सरकार को क्या लाभ होगा?

₹एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र₹ केवल पत्रकारों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सरकार के पास देशभर के सक्रिय पत्रकारों का अद्यतन और प्रमाणित डाटा उपलब्ध होगा। इससे विभिन्न योजनाओं का संचालन, संवाद कार्यक्रमों का आयोजन, मीडिया समन्वय और संकट की परिस्थितियों में सूचना प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा। इसके अतिरिक्त फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। लोकतंत्र को कैसे मिलेगा लाभ?

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता से सवाल पूछना, समाज की आवाज बनना और जनहित के मुद्दों को सामने लाना है। जब पत्रकार की पहचान स्पष्ट और विश्वसनीय होगी तो उसकी बात का प्रभाव भी बढ़ेगा। एक प्रमाणित पहचान व्यवस्था से मीडिया और समाज के बीच भरोसा मजबूत होगा। जनता को भी यह विश्वास रहेगा कि सामने मौजूद व्यक्ति वास्तव में पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ है। यह व्यवस्था पत्रकारिता के पेशेवर मानकों को भी मजबूत करेगी और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहन देगी।

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

हालांकि ₹एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र₹ की अवधारणा आकर्षक और उपयोगी है, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी आवश्यक होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध न बन जाए। पत्रकार की मान्यता का अधिकार सरकार के हाथों में अत्यधिक केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो स्वतंत्र पत्रकारों, डिजिटल पत्रकारों और छोटे मीडिया संस्थानों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और बहुस्तरीय होनी चाहिए। इसमें मीडिया संगठनों, प्रेस परिषद, पत्रकार संगठनों, डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डिजिटल युग की जरूरत

भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आधार, डिजिलॉकर, फास्टैग, आयुष्मान कार्ड और डिजिटल पहचान की अनेक सफल व्यवस्थाएं इसका उदाहरण हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए भी एक सुरक्षित, डिजिटल और राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित पहचान प्रणाली विकसित करना असंभव नहीं है। यह व्यवस्था मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी हो सकती है, जिससे पहचान का सत्यापन कुछ ही सेकंड में संभव हो।

विश्व के अनुभव

दुनिया के अनेक देशों में पत्रकारों की मान्यता और पहचान के लिए व्यवस्थित तंत्र मौजूद हैं। हालांकि हर देश का मॉडल अलग है, लेकिन अधिकांश जगहों पर पत्रकार की पहचान का सत्यापन किसी न किसी संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भी ऐसा मॉडल विकसित किया जा सकता है जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और पहचान की विश्वसनीयता के बीच संतुलन स्थापित करे।

अब बहस नहीं, पहल का समय

आज पत्रकारिता अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। एक ओर सूचना क्रांति ने खबरों के प्रसार को आसान बनाया है, तो दूसरी ओर फर्जी पहचान, अपुष्ट सूचनाएं और पत्रकारिता की आड़ में होने वाली गतिविधियों ने पेशे की साख को चुनौती दी है। ऐसे समय में ₹एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र₹ की अवधारणा गंभीर राष्ट्रीय विमर्श का विषय बननी चाहिए। इसका उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि वास्तविक पत्रकारों की पहचान को सम्मान, सुरक्षा और वैधता प्रदान करना होना चाहिए। यदि पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित की जाती है तो इससे पत्रकारों, सरकार, प्रशासन और आम जनता–सभी को लाभ होगा। इससे पत्रकार हितों से जुड़ी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फर्जी पत्रकारिता पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया की विश्वसनीयता अनिवार्य है। और विश्वसनीयता की पहली शर्त है–स्पष्ट और प्रमाणित पहचान। इसलिए अब समय आ गया है कि देश ₹एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र₹ जैसी व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करे और पत्रकारिता को एक नई संस्थागत मजबूती प्रदान करे।

शहरीकरण की दौड़ और अकेलापन : भीड़ में भी तनहा इंसान

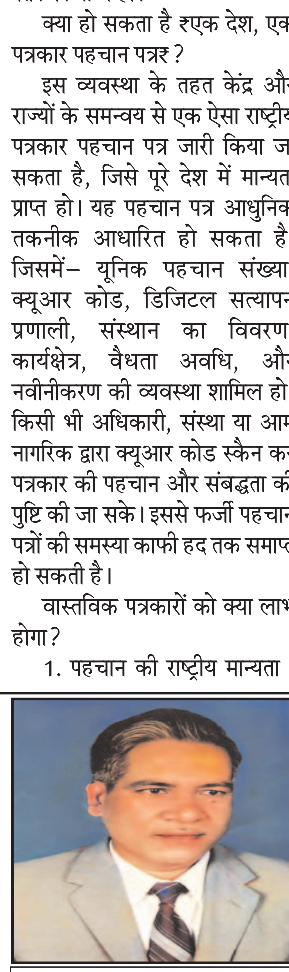
-विक्रम दयाल

विक्रम दयाल

रात के दस बजे हैं। सड़कों पर अब भी गाड़ियों की रफ्तार थमी नहीं है, ऊँची इमारतों की खिड़कियों से रोशनी झर रही है, और शहर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जाग रहा है। इस चकाचौंध में सब कुछ जीवंत लगता है–पर इसी जीवंतता के बीच एक अजीब सन्नाटा भी पसरा है। यह सन्नाटा बाहर नहीं, लोगों के भीतर है। यह उस अकेलेपन की आवाज है, जो भीड़ के बीच भी इंसान को तनहा कर देती है। शहरों की ओर भागती यह दुनिया अवसरों की तलाश में निकली है–बेहतर नौकरी, बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य। लेकिन इस बेहतर की तलाश में हमने क्या खो दिया, यह सवाल अक्सर अनसुना रह जाता है। गाँवों और छोटे कस्बों की सहजता, रिश्तों की गर्माहट और अपनापन–सब कुछ पीछे छूट जाता है, और सामने रह जाती है एक ऐसी जिंदगी, जहाँ हर कोई अपने-अपने लक्ष्य की दौड़ में व्यस्त है।

शहरीकरण ने हमें सुविधाएँ तो दी हैं, लेकिन समय छीन लिया है। अब लोगों के पास मिलने का समय नहीं, बातें करने का धैर्य नहीं, और किसी के दुख-सुख को समझने की फुर्सत नहीं। पड़ोसी एक-दूसरे के नाम तक नहीं जानते, और एक ही घर में रहने वाले लोग भी अलग-अलग कमरों में अपनी-अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। यह दूरी केवल भौतिक नहीं, भावनात्मक भी है। सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ता है, जो अपने घर-परिवार से दूर इस शहर में नई शुरूआत करते हैं। शुरूआत में यह शहर उन्हें सपनों की तरह लगता है, लेकिनधीरे-धीरे वही शहर एक अजनबी सा लगने लगता है। हजारों चेहरों के बीच भी कोई अपना नहीं होता, जिससे दिल की बात कही जा सके। यही एहसास धीरे-धीरे अकेलेपन में बदल जाता है। तकनीक ने इस दूरी को कम करने का दावा जरूर किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने कई बार इस दूरी को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होने के बावजूद, असली जीवन में बात करने के लिए कोई एक व्यक्ति भी नहीं होता। आभासी जुड़ाव असली संबंधों की कमी को पूरा नहीं कर पाता। यह अकेलापन केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है। यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आत्मविश्वास को कम करता है और कई बार व्यक्ति को भीतर ही भीतर तोड़ देता है। लेकिन क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? है–और वह हमारे ही व्यवहार में छिपा है। हमें फिर से रिश्तों को समय देना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, और अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। एक छोटी-सी बातचीत, एक सच्ची मुस्कान, या किसी की बात ध्यान से सुन लेना–ये छोटे-छोटे कदम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि शहर केवल इमारतों और सड़कों का नाम नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों का भी है। अगर हम एक-दूसरे के लिए समय निकालें, तो यही शहर अपनापन भी दे सकता है। अंततः, शहरीकरण की यह दौड़ हमें आगे जरूर ले जा रही है, लेकिन अगर इस दौड़ में हम अपने रिश्ते और भावनाएँ खो दें, तो यह प्रगति अधूरी रह जाएगी। संदेश यही है–भीड़ में खोने के बजाय, किसी का सहारा बनिए; क्योंकि सच्चा जुड़ाव ही अकेलेपन को मिटा सकता है।

मध्य रेल के टिकट चेकिंग टीम ने फर्जी आरपीएफ कर्मी को पकड़ा

मुंबई। मध्य रेल की यात्रा टिकट निरीक्षक श्रद्धा सालुंखे और केतकी कदम ने आठ जून को मुंबई मंडल के मानखुर्द और वडाला रोड स्टेशनों के बीच चलने वाली एसी लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मी होने का ढोंग कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। श्रीमती सालुंखे और श्रीमती कदम आठ जून की शाम को एसी लोकल में ड्यूटी पर थीं, जब उन्होंने एक यात्री का टिकट चेक किया। यात्री ने खुद को आरपीएफ कर्मी बताया और आरपीएफ आईडी कार्ड दिखाया, लेकिन कोई यात्रा प्राधिकरण नहीं दिखा सका। उसके आईडी कार्ड से भी संदेह पैदा हुआ और कुछ सवालों के जवाब न दे पाने से उनका संदेह और पुख्ता हो गया। यात्री ने अपना नाम एम डी मलंग बताया और उसे हिरासत में लेकर तुरंत आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया। लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 (बीएनएस) की धारा 204, 337, 339, 340(2), 319(2), 318(4) और 137 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए फर्जी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। मध्य रेलवे सभी यात्रियों और कर्मचारियों से सतर्क रहने की अपील करता है। सरकारी कर्मचारियों का रूप धारण करना एक आपराधिक अपराध है। असली आरपीएफ कर्मियों के पास आधिकारिक पहचान पत्र होना चाहिए और उन्हें टिकट चेकिंग ड्यूटी में सहयोग करना चाहिए। रेलवे कर्मचारी होने का दावा करने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन 139, निकटतम आरपीएफ चौकी या ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी को दी जानी चाहिए।

पालघर संत हत्याकांड के दोषियों को कब मिलेगी सजा?, पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। पालघर संत हत्याकांड में मारे गए संतों एवं चालक के परिजनों ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, हत्याकांड के दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने तथा पालघर में दिवंगत संतों का स्मारक बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। समाजसेवी अरुण शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में चालक तेलंगडे की माता निर्मला तेलंगडे एवं उनके दो अबोध बच्चे, संत सुशील गिरि की बहन सपना मिश्रा तथा सहयोगी बृजेश पांडे शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष घटना से प्रभावित परिवारों की वर्तमान स्थिति और उनकी समस्याओं को विस्तार से रखा। अरुण शुक्ला ने बताया कि परिजनों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पीड़ित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, मामले के सभी दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जाए तथा पालघर में दिवंगत संतों की स्मृति में एक भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन पांडे एवं विधायक संजय उपाध्याय के सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि पालघर में संतों और उनके चालक की भीड़ द्वारा की गई हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। घटना के वर्षों बाद भी परिजन न्याय, सम्मान और पुनर्वास की मांग को लेकर प्रयासरत हैं तथा मुख्यमंत्री से हुई यह मुलाकात उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

नयानगर क्षेत्र में विदेशी नागरिक से 78.45 लाख रुपये की कोकीन जब्त

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की एंटी-नारकोटिक्स सेल-1 ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक के कब्जे से 261.5 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 78 लाख 45 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एंटी-नारकोटिक्स सेल-1 की टीम 9 जून 2026 को अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मीरा रोड पूर्व स्थित एस.के. स्टोन से मीरा रोड रेलवे स्टेशन होते हुए पूनम सागर जाने वाले मार्ग पर स्थित ईशा वाइन शॉप के पास एक विदेशी नागरिक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोककर पूछताछ की और नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 261.5 ग्राम वजन की कोकीन बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 78.45 लाख रुपये आंकी गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी नाइजीरिया का नागरिक है और मूल रूप से एनुगु का निवासी है। वह उक्त मादक पदार्थ बिक्री के उद्देश्य से अपने पास रखे हुए था। पुलिस ने बरामद कोकीन को पंचनामा कर जब्त कर लिया तथा आरोपी के खिलाफ नयानगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 232/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच नयानगर पुलिस द्वारा की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, पुलिस उपायुक्त (अपराध) संदीप डोईफोडे तथा सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में संपन्न की गई।

प्राकृतिक नाले पर अतिक्रमण हटाने की मांग, पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी ने मनपा को सौंपा पत्र

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव उत्तमराव नाइक ने पेनकरपाड़ा के लोअर पाड़ा क्षेत्र में प्राकृतिक नाले पर किए गए कथित अतिक्रमण को लेकर मीरा-भायंदर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-6 के मंडल अधिकारी को पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में नाइक ने आरोप लगाया है कि पेंकर पाड़ा लोअर पाड़ा स्थित एक प्राकृतिक नाले पर कल्पतरु नामक डेवलपर द्वारा बड़ी शीट शेड खड़ी कर दी गई है तथा वहां लोहे के कंटेनर और सरिया रखकर नाले के प्रवाह को बाधित किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की कई हाउसिंग सोसायटियों का सांडपानी (सीवेज) छोटे सीवरों के माध्यम से इसी प्राकृतिक नाले में प्रवाहित होता है। पत्र के अनुसार, नाले पर किए गए इस अवरोध के कारण सफाई कर्मचारियों को नाले में जमा कचरा निकालने में कठिनाई हो रही है। इससे आगामी मानसून के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई है। उत्तमराव नाइक ने बताया कि इस संबंध में 5 जून 2026 को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को भी शिकायत दी गई थी। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को अतिक्रमण विभाग के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि प्राकृतिक नाले पर लगाए गए शीट शेड, लोहे के कंटेनर और अन्य अवरोधों को तत्काल हटाकर नाले की सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के मौसम में स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग की होगी।

4 करोड़ 65 लाख की ठगी मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत पर 12 जून को फैसला

कल्याण (उत्तरशक्ति)। बिजनेस प्लान के नाम पर 300 से अधिक लोगों से करीब 4 करोड़ 65 लाख रुपये की ठगी कर दुबई फरार हुए मुख्य आरोपी रवी महाशेठ समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी प्रकरण में फरार आरोपी रवी महाशेठ की बहन किरण और बहनोई अमरकांत दुबे ने कल्याण अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं। सरकारी वकील संजय मोरे के अनुसार, इस अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला 12 जून को सुनाया जाएगा। सरकारी पक्ष के अनुसार, कोरोना काल के दौरान बदलापुर निवासी रवी महाशेठ, उसकी पत्नी और अन्य पांच लोगों ने मिलकर समृद्धि मल्टीट्रेड प्रा. लि. नामक कंपनी बनाई थी। इस कंपनी में सनी पगारे समेत करीब 300 से अधिक लोगों ने निवेश किया था। आरोप है कि आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से निवेश करवाया और बाद में एक के बाद एक कंपनियां बंद कर नई कंपनियां शुरू कर निवेशकों को गुमराह किया।

जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो रवी महाशेठ, उसकी पत्नी और अन्य साथी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रवी महाशेठ नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया। सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी कि इस धोखाधड़ी में किरण और अमरकांत की भी भूमिका है। उनकी गिरफ्तारी से फरार मुख्य आरोपी तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि दोनों आरोपी केवल रिश्तेदार हैं और उनका इस अपराध में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कल्याण जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश-1 परवीन सैयद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 12 जून को सुनाया जाएगा।

इंस्ट्राग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग छात्रा से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार

लव जिहाद बता भड़का बजरंग दल, कहा बर्दाश्त नहीं हो कड़ी कार्यवाही

-अजीत सिंह

पालघर (उत्तरशक्ति)। पालघर में 16 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का सनसनी खेज मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर बोईसर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी रियाज शेख (24) ने इंस्ट्राग्राम पर दोस्ती कर प्रेम और विवाह का झांसा देकर पीड़िता को अपने जाल में फंसाया तथा बाद में उससे दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकताओं से पीड़िता तथा उसके परिवार ने संपर्क किया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों की मदद से पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।वहीं, विहिप के विभाग मंत्री चंदन सिंह ने कहा, ?नाबालिग बेटियों को झूठे प्रेमजाल में फंसाकर उनका शोषण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। विहिप नेता मुकेश दुबे ने इसे ?लव जिहाद? का मामला बताते हुए कहा कि प्रेम और विवाह का झांसा देकर नाबालिग बालिकाओं को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दुबे ने कहा कि विहिप और बजरंग दल पीड़िता तथा उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिला मंत्री जयेश घरत,काचू शेट्टी,दीपेश दांडेकर, आकाश नारखेडे, प्रभात ठाकूर,विजय शेट्टी, सागर शर्मा मौजूद रहे। बोईसर के सहायक पुलिस निरीक्षक सतिश अस्वर ने कहा कि आरोपी पर केस दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। ज्ञात हो कि दहानू के चर्चित दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग प्रकरण के बाद अब बोईसर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदू संगठनों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। विहिप और बजरंग दल ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नालासफाई ठेकेदार ने केडीएमसी इंजीनियर को दी धमकी

ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की जोरदार मांग

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण- डोंबिवली महा नगरपालिका (केडीएमसी) क्षेत्र में नालेसफाई का मुद्दा बुधवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में जोरदार तरीके से उठा। बैठक में खुलासा हुआ कि लोकग्राम इलाके में नालेसफाई का काम कर रहे ठेकेदार जितू आहूजा ने महापालिका के उप-अभियंता उमेश भट को धमकी दी है। खुद उप-अभियंता भट ने बताया कि उन्होंने अब तक संबंधित ठेकेदार को सात नोटिस जारी किए हैं।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे और मंदार हळबे ने सरकारी काम में बाधा डालने और अधिकारी को धमकाने वाले ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि महापालिका प्रशासन इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं। यह पूरा मामला स्थायी समिति के सभापति मल्लेश शेट्टी के प्रभाग का है। सभापति शेट्टी पहले ही नालेसफाई के काम को लेकर नाराजगी जता चुके थे। इसके बाद यह मामला सामने आया है। उप-अभियंता भट ने ठेकेदार के दबाव के बावजूद काम में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए और नोटिस जारी किए, लेकिन ठेकेदार ने कोई जवाब नहीं दिया। सदस्यों ने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी के साथ प्रशासन को मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। नालेसफाई ठीक से नहीं होने का मुद्दा भाजपा सदस्य विकास म्हात्रे ने भी उठाया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में एक बड़े नाले का ढक्कन खुला होने के कारण पिछले वर्ष एक बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

बैठक में यह भी मुद्दा उठा कि नाले से निकाला गया गाद (सिल्ट) शहर में कहीं भी नहीं फेंका जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दीपेश म्हात्रे ने कहा कि अगर आम नागरिकों पर कचरा फेंकने के लिए कार्रवाई हो सकती है, तो ठेकेदारों पर भी सख्ती होनी चाहिए। घनकचरा व्यवस्थापन विभाग के उपायुक्त रामदास कोकरे से भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं कार्यकारी अभियंता प्रसाद सखदेव ने जानकारी दी कि नालेसफाई का काम चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर लोग नालों में कचरा डालते हैं, जिससे समस्या बनी रहती है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत बताई। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका और कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

शिवसेना शिंदे गुट के विभाग प्रमुख भाजपा मे शामिल

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति) मीरा भायंदर शिवसेना शिंदे गुट के मीरा भायंदर जिला शहर के विभाग प्रमुख बिपिन चौधरी सैकड़ो कार्यकताओं के साथ भाजपा मे शामिल हुए। बिपिन चौधरी की मीरा भायंदर की राजनीति मे अपनी अलग पहचान है और कार्यकताओं मे अच्छी पकड़ है ! भाजपा मीरा भायंदर के विधायक नरेंद्र मेहता, जिलाध्यक्ष दिलीप जैन, महामंत्री बृजेश तिवारी, परिवहन समिति अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा के समक्ष जिला कार्यालय मे पक्ष प्रवेश किया ! पक्ष प्रवेश करने पर विपिन चौधरी ने कहा की विधायक नरेंद्र मेहता के कार्य करने की शैली से प्रभावित होकर मैंने भाजपा मे अपने साथियों के साथ शामिल हुआ हु। विपिन चौधरी के साथ अनिरुद्ध राय, रवि शेट्टी, राजन शुक्ला, प्रेमानन्द मिश्रा, एड अविनायक पाल, डी. बी. सिंह के साथ भारी संख्या मे शिवसैनिको ने भाजपा का दुपट्टा पहना कर मीरा भायंदर मे कुछ महीनों से दोनों पार्टियों के कार्यकर्त्ता एक दूसरे का दामन पकड़ रहे है जब विधानसभा मे दोनों पार्टी आपसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन महानगर पालिका चुनाव मे दोनों पार्टियां कोई गठबंधन नहीं करती है।

घोड़बंदर की शिवश्रुति परियोजना का विकास अब एमटीडीसी के माध्यम से: प्रताप सरनाईक

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि घोड़बंदर में 'शिवस्त्रुति' परियोजना का काम, जो कई वर्षों से रुका हुआ था, अब महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) के माध्यम से तेज गति से पूरा किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई के कार्यालय में आयोजित एक बैठक में इस संबंध में बात की। बैठक में पर्यटन सचिव संजय खंडारे, मीरा भायंदर नगर निगम आयुक्त राधा बिनोद शर्मा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में, मैं पर्यटन के लिहाज से घोड़बंदर किले और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोड़बंदर किले, खाड़ी तट और उस तरफ स्काई वॉक जैसी विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई थी। घोड़बंदर किले के क्षेत्र के विकास से पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के अनुरूप, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घोड़बंदर किले की तलहटी में 'शिवस्त्रुति' के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत वाली 'शिवस्त्रुति' परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत पर्यटन विभाग द्वारा और शेष 25 प्रतिशत संबंधित संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा। नगर निगम के माध्यम से इसे उपलब्ध कराने का निर्णय एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा लिया गया था। हालांकि, मैंने पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई से अनुरोध किया था कि निर्णय लेने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने और परियोजना कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए संपूर्ण लागत पर्यटन विभाग द्वारा वहन की जानी चाहिए। आज हुई बैठक में मंत्री शंभूराज देसाई ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तदनुसार, घोड़बंदर में स्थापित होने वाली 'शिवस्त्रुति' परियोजना का संपूर्ण खर्च पर्यटन विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) द्वारा वहन किया जाएगा। इससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्य में तेजी आएगी और इसके शीघ्र पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों के साथ-साथ पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई को परियोजना में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

भिवंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य महाआरती

भिवंडी । देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा भिवंडी शहर इकाई की ओर से पद्मानगर स्थित राम मंदिर में विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा शहर अध्यक्ष रवि सावंत एवं भाजपा गटनेता संतोष शेट्टी की प्रमुख उपस्थिति रही। महाआरती में प्रभाग समिति सभापति रंजिता मोहन कोंडा, नगरसेविका दीपा दीपक मढवी, श्याम भोईर, एडवोकेट नंदन गुप्ता, एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, कोंका मल्लेश्याम, सुगंधा टावरे, मीना कुंटे, कल्पना शर्मा, ममता परमाणी, सत्वशीला जाधव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं और कार्यकताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीघार्यु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए विशेष प्रार्थना की। भाजपा गटनेता संतोष शेट्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है और देश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी के सफल नेतृत्व में भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का सम्मान बढ़ा है। महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घ एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीघार्यु होने के लिए बोरीवली में आयुष्यवर्धक हवन सम्पन्न

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल एवं ऐतिहासिक 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीघार्यु होने एवं राष्ट्रसेवा के संकल्प की निरंतरता हेतु आयुष्यवर्धक हवन का बोरीवली में आयोजन में हुआ। भारतीय जनता पार्टी, बोरीवली- पश्चिम मंडल द्वारा श्री अंबामाता मंदिर, फैक्ट्री लेन, बोरीवली-पश्चिम में आयोजित इस हवन के अवसर पर उत्तर मुम्बई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय व अनेक नगरसेवक, मुंबई एवं जिला स्तर के भाजपा पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।

स्नेहा दुबे पंडित ने पालघर कलेक्टर के साथ विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर की चर्चा

पालघर। जिला कलेक्टर कार्यालय, कोलगांव (पालघर) में आज वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने जिला कलेक्टर श्रीमती इंदुरानी जाखड़ तथा निवासी उप जिला कलेक्टर सुभाष भागड़े के साथ सद्भावना बैठक की। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सप्ताला में उपकेंद्र की स्थापना, ग्राम पंचायत सीमा में अवैध निमार्णों का मुद्दा, बावखल संरक्षण, मालोंडे सर्वे नंबर 84 से संबंधित विषय, प्रांतीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, वसई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र सहित कई विकास परियोजनाओं पर सकारात्मक विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विरारझअलीबाग कॉरिडोर परियोजना की विस्तृत समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान भाजपा वसई-विरार शहर जिला महासचिव बिजेंद्र कुमार, मयंक शेठ और नंदू पवार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर क्षेत्र के विकास को गति देने के उपायों पर विचार किया गया। स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि वसई क्षेत्र के समग्र विकास और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी है तथा जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले की तरह मजबूत बनी हुई है।

विधायक राजेश मोरे भी मोर्चे में शामिल

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण ग्रामीण क्षेत्र के लोढा हेवन इलाके में फेरीवालों और साप्ताहिक बाजार से हो रही परेशानी के विरोध में शिंदे सेना ने ई प्रभाग कार्यालय पर जोरदार मोर्चा निकाला। आरोप है कि इस मामले में ई प्रभाग के सहायक आयुक्त सचिन तामखेडे द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

यह मोर्चा शिंदे सेना के नगरसेवक गजानन पाटील के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें शिंदे गुट के विधायक राजेश मोरे भी शामिल हुए। इस दौरान विधायक मोरे और नगरसेवक पाटील ने कहा कि महायुति की सत्ता होने के बावजूद स्थानीय नागरिकों को फेरीवालों से परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसलिए यह आंदोलन करना पड़ा।

करीब एक महीने पहले कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे ने महापालिका में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान फेरीवालों को हटाने और साप्ताहिक बाजार बंद करने के निर्देश दिए थे। नगरसेवक पाटील की इस मांग को उचित मानते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे। बावजूद इसके, लोढा हेवन क्षेत्र में न तो फेरीवालों को हटाया गया और न ही साप्ताहिक बाजार बंद किया गया।

आरोप है कि सहायक आयुक्त तामखेडे प्रशासनिक निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सांसद और विधायक के आदेशों की अनदेखी करना गंभीर मामला है। नगरसेवक गजानन पाटील ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो शिंदे सेना इससे भी उग्र आंदोलन करेगी। यह मोर्चा दोपहर में निकाला गया था। वहीं शाम के समय प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि लोढा हेवन क्षेत्र में सहायक आयुक्त सचिन तामखेडे द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

सड़क पर बिखरे सरसों के तेल से फिसले आधा दर्जन बाइक सवार, 10 लोग घायल

रियाजुल हक

गौराबादशाहपुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर पंचायत गौराबादशाहपुर के नयनसंड मोड़ पर मंगलवार की सुबह सड़क पर गिरे सरसों के तेल ने कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी। सड़क पर फैले तेल के कारण संतुलन बिगड़ने से आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार फिसलकर गिर गए, जिससे करीब 10 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह किसी अज्ञात वाहन से सड़क पर सरसों का तेल गिरकर काफी दूर तक फैल गया था। सड़क चिकनी हो जाने के कारण वहां से गुजरने वाले बाइक सवार एक-एक करके गिरते रहे। गनीमत रही कि सभी घायलों को मामूली चोटें ही आईं। सभी घायलों ने स्थानीय स्तर पर ही निजी चिकित्सकों के यहां मरहम-पट्टी कराई और प्राथमिक उपचार के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। समाचार लिखे जाने तक किसी भी घायल का नाम व पता स्पष्ट नहीं हो सका है।

लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई। सड़क पर फैले तेल के कारण और अधिक लोगों के गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों ने उस पर राख और मिट्टी डाली, जिससे सड़क का फिसलन कम हुआ और आवागमन सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के प्रति प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सड़क की उचित सफाई कराए जाने की मांग की है।

10 हजार रुपये रिश्वत लेते बीएसए कार्यालय का बाबू गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक आकाश यादव को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, आरोपी कर्मचारी एक शिक्षक से विद्यालय की मान्यता दिलाने के नाम पर अवैध धनराशि की मांग कर रहा था। रिश्वत की लगातार मांग से परेशान शिक्षक ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन संगठन से की थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने जांच और सत्यापन किया,

जिसमें आरोप सही पाए गए।

इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। शिकायतकर्ता को आरोपी के संपर्क में भेजा गया और जैसे ही आकाश यादव ने 10 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाया गया। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस प्रकरण में किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता तो नहीं है।

एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बीएसए कार्यालय सहित पूरे शिक्षा विभाग में दिनभर इस घटना की चर्चा होती रही। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।

दूल्हा हत्याकांड और एनकाउंटर मामले को लेकर भारतीय मानव समाज पार्टी का प्रदर्शन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूल्हे आजाद बिंद

हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तथा गाजीपुर में कमलेश बिंद के पुलिस एनकाउंटर मामले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपकर दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि 1 मई 2026 को बारात लेकर जा रहे दूल्हे आजाद बिंद की हत्या कर दी गई थी। घटना के काफी समय बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे पीड़ित परिवार और समाज में आक्रोश व्याप्त है। संगठन ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की।

वहीं, गाजीपुर में कमलेश बिंद के पुलिस एनकाउंटर को लेकर भी संगठन ने सवाल खड़े किए। पार्टी का कहना है कि मुठभेड़ की परिस्थितियों और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर पीड़ित परिवार तथा समाज के लोगों में संदेह है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

ज्ञापन में जौनपुर हत्याकांड के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने, गाजीपुर एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है।

भारतीय मानव समाज पार्टी ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने की अपील की है, ताकि दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

साइबर ठगी के शिकार को 24 घंटे में मिली राहत खाते में लौटे पूरे रुपए

सोनभद्र(उत्तरशक्ति)। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच बीजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक पीड़ित ग्रामीण को बड़ी राहत दिलाई है। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए ग्रामीण के खाते से निकाली गई पूरी धनराशि वापस कराकर पुलिस ने अपनी सक्रियता और कार्यकुशलता का परिचय दिया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम नेमना निवासी जियानन्द पुत्र दशरथ किसी अज्ञात साइबर ठग के झांसे में आ गए थे, जिसके चलते उनके बैंक खाते से 2000 रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई। घटना की जानकारी होते ही पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर अपराध नियंत्रण अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी दुद्धी के मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बीजपुर थाना की साइबर टीम ने तत्काल जांच शुरू की। जांच

के दौरान टीम ने एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से ठगी गई धनराशि को होल्ड कराया तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर एमआरएम पोर्टल के जरिए संबंधित बैंक को धनराशि वापस कराने हेतु अनुरोध भेजा।

पुलिस की तत्पर और प्रभावी कार्रवाई का सकारात्मक परिणाम सामने आया और 9 जून को पीड़ित जियानन्द के बैंक खाते में पूरे 2000 रुपये वापस जमा हो गए। अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने पर पीड़ित ने बीजपुर पुलिस एवं साइबर टीम का आभार व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की। इस सराहनीय कार्रवाई में थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक कमलाकान्त पाण्डेय, साइबर हेल्प डेस्क के कांस्टेबल सरोज अमित कुमार श्रीकृष्ण तथा महिला कांस्टेबल निहारिका पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर घबराएं नहीं बल्कि तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर धनराशि को सुरक्षित कराया जा सके।

यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने गौरी शंकर धाम में की विशेष पूजा-अर्चना

गौरी शंकर धाम मंदिर में गूंजे बाबा भोलेनाथ के जयकारे, सांसद ने देश की खुशहाली और पीएम की दीघार्यु के लिए की प्रार्थना

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। देश के यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर आज जौनपुर के सुप्रसिद्ध और आस्था के प्रमुख केंद्र श्री गौरी शंकर धाम मंदिर में एक भव्य एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने बाबा भोलेनाथ का विधिवत जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना की।

सांसद सीमा द्विवेदी ने पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच देश की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य व दीघार्यु जीवन के लिए मंगल कामना की।

सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण का स्वर्णिम युग: सीमा द्विवेदी

इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष भारत के इतिहास में 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' के स्वर्णिम अध्याय हैं आज भारत वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभरा है। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, भव्य राम मंदिर का निर्माण, और देश के करोड़ों गरीबों को पक्के

मकान, राशन, स्वास्थ्य बीमा व सम्मानजनक जीवन देना मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि आज का यह आयोजन केवल एक राजनीतिक उत्सव नहीं, बल्कि देश के प्रधान सेवक के प्रति जनता के अगाध प्रेम और कृतज्ञता को प्रकट करने का माध्यम है गौरी शंकर धाम की यह पावन भूमि आज इस संकल्प की साक्षी बनी है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 'विकसित भारत' बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।

उक्त अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अजय सरोज मंडल अध्यक्ष संतोष पासी सुधीर तिवारी शिव प्रकाश सिंह श्रीमती सुमन द्विवेदी मनोज द्विवेदी शिवम्‌ सिंह चंचल सिंह दीपक तिवारी दिनेश मिश्रा पप्पू मिश्रा अंजनी तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक व पार्टी के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

8 दिन जेल में रखने पर 2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। शांति भंग की धाराओं के दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और किसी भी व्यक्ति को वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना जेल नहीं भेजा जा सकता। अदालत ने प्रयागराज के मंसूर अहमद उर्फ लल्लू को आठ दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में 2 लाख रुपये

शांति भंग में निर्दोष को जेल भेजा तो खैर नहीं! दोषी अफसर की सैलरी से रोज कटेंगे 25 हजार रुपये, इलाहाबाद HC का आदेश

मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि मंसूर अहमद को खीरी क्षेत्र से उठाकर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए एक प्रोफार्मा आदेश के आधार पर सीधे जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मंसूर अहमद को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश देते हुए कहा कि यह राशि संबंधित दोषी तत्कालीन एसीपी के वेतन से वसूली जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले को पुलिस कार्रवाई में जवाबदेही तय करने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

लापरवाही पर सब इंस्पेक्टर निलंबित, विभागीय जांच के आदेश

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। जनपद में पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में तैनात एक उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा के दौरान संबंधित उपनिरीक्षक के कार्यों में गंभीर लापरवाही सामने आई। जांच में पाया गया कि उन्होंने एक हिस्ट्रीशीटर की निगरानी में अपेक्षित रुचि नहीं ली तथा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार

उससे संबंधित सामान्य डायरी (जीडी) और फ्लाईशीट में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज नहीं कीं। इसके अलावा विभिन्न गंभीर मामलों में प्रभावी कार्रवाई न करने, मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करने तथा साइबर हेल्प डेस्क पर 30 से अधिक लंबित शिकायतों के निस्तारण में उदासीनता बरतने के तथ्य भी प्रकाश में आए। एसएसपी ने इसे पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए संबंधित उपनिरीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ करें। ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा और बेहतर पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक पर दो अज्ञात लाशें से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पहली घटना मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के नएपुरा गांव में स्थित रेलवे ट्रैक पोल नम्बर 325 पर पाई गई है। इस अज्ञात पुरुष की उम्र लगभग 50 वर्ष बताया गया है, जो सफेद रंग की पैंट सफेद चप्पल पहने हुए हैं। जिसका कद औसद रंग गेहूवा बताया गया है। मौके पर जफराबाद जीआरपी पुलिस और और स्थानीय मड़ियाहूं कोतवाली पुलिस दोनों मौके पर मौजूद रही और पहचान कराने का काफी प्रयास किया लेकिन पहचान नहीं हो सकी। इसी क्रम में मीरगंज थाने की पुलिस ने अपने क्षेत्र के मोदपुर बनकट गांव स्थित रेलवे ट्रैक पर बुधवार तड़के एक अज्ञात व्यक्ति की लाश ट्रेन से कटी अवस्था में पाई गई है जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष आंकी गई है। पुलिस ने लाश को रखकर काफी देर तक पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने दोनों लाशों को जिला अस्पताल के लाश घर में रखवा दिया ताकि जिसके घर का आदमी खोया हुआ हो वह जाकर पहचान कर सके।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के आदर्शों पर चलकर समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव: अरशद खान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहम्मद अरशद खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर सामाजिक न्याय मंच, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी एवं पूर्व विधायक जौनपुर सदर ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भारतीय इतिहास की महानतम शासकों में से एक थीं। उन्होंने न्याय, समता, सेवा, लोककल्याण और धार्मिक सहिष्णुता के आदर्शों को अपने शासन की आधारशिला बनाया।

उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर ने समाज के कमजोर, वंचित और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। उनके शासनकाल में जनता को त्वरित न्याय, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने देश के अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्निर्माण

कर भारत की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने का कार्य किया।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि आज के समय में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के विचार और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। समाज में बढ़ती असमानता, भेदभाव और सामाजिक विभाजन को समाप्त करने के लिए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के जीवन, संघर्ष, सेवा और न्याय के सिद्धांतों का अध्ययन करें तथा समाज में भाईचारा, सद्भाव और समानता स्थापित करने के लिए आगे आएं। आज अखिलेश यादव जी लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के सपनो को साकार करने के लिए सभी जातियों को आबादी के अनुपात में शासन प्रशासन व राजनीति में भागीदारी दिलाने के संकल्प के साथ पूरे देश में काम कर रहे हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

पंचायत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, 10 जून से निरीक्षण के लिए उपलब्ध

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जौनपुर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं जिलाधिकारी जौनपुर सैमुअल पॉल एन. द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशों के क्रम में पंचायत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन मंगलवार 10 जून 2026 को कर दिया गया।

जारी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची जनपद के सभी विकास खंड कार्यालयों, ग्राम पंचायत कार्यालयों, पंचायत भवनों, विद्यालयों, साधन सहकारी समितियों के भवनों, उचित मूल्य की दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य नामित सार्वजनिक भवनों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

जिला प्रशासन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाता 10 जून 2026 से संबंधित कार्यालयों में जाकर मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचक नामावली की एक प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) जौनपुर द्वारा जारी प्रपत्र-7 के अनुसार जनपद की सभी ग्राम पंचायतों एवं उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का संशोधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची 10 जून 2026 से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं तथा जिला सूचना अधिकारी को इस सूचना का प्रकाशन सभी दैनिक समाचार पत्रों में कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

जन-जागरूकता अभियान के तहत ग्राम सभाओं में जनसंवाद, प्लास्टिक मुक्त तालाब अभियान चला

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद में 8 जून से 14 जून तक समेकित जन कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत बुधवार को जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर जनसमस्याओं के समाधान एवं सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य किया गया।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि मलिन बस्तियों में खुली बैठकें आयोजित कर लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। ₹सरकार आपके द्वार₹ कार्यक्रम के तहत जन समस्या समाधान शिविर भी लगाए गए।

अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अस्वच्छ सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। वहीं 'प्लास्टिक मुक्त तालाब अभियान' के तहत तालाबों से प्लास्टिक कचरा हटाकर उनके सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया।

अभियान के दौरान लगभग 100 कुंतल से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया गया, जिसका समुचित निस्तारण कराया गया। प्रशासन ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

रेलवे स्टेशन के यूपीएस रूम में लगी भीषण आग, विद्युत उपकरण जलकर खाक

राम कुमार गुप्ता

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। विंढमगंज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित यूपीएस इलेक्ट्रॉनिक रूम में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा यूपीएस रूम उसकी चपेट में आ गया और अंदर रखे विद्युत उपकरण जलकर नष्ट हो गए।

जानकारी के अनुसार दोपहर करीब एक बजे स्टेशन परिसर से धुआं और आग की लपटें उठती देख रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और ग्रामीणों ने हैंडपंप एवं समरसेबल के पानी से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।

गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग की चपेट में आने से यूपीएस रूम में स्थापित कई महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए।

प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई तथा नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है।

रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। घटना के बाद स्टेशन परिसर में सुरक्षा

रेणुकूट व्यापार मंडल का संगठन विस्तार, 41 सदस्यीय कार्यकारिणी

रेणुकूट, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। नगर के शिव पार्क स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को रेणुकूट व्यापार मंडल की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष बृज किशोर ने की। इस दौरान संगठन को मजबूत एवं प्रभावी बनाने के साथ-साथ व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में संगठन विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पांच उपाध्यक्ष, पांच मंत्री, महामंत्री, संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी सहित विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। इसके अलावा संरक्षक मंडल में छह, मार्गदर्शन मंडल में तीन तथा एक विधि सलाहकार को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही 13 लोगों को साधारण सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

इस प्रकार रेणुकूट व्यापार मंडल की कुल 41 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। पदाधिकारियों ने व्यापारियों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान और संगठन को अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने का संकल्प लिया।

बैठक का संचालन अमरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर केश नाथ, अरुण पांडे, फकीर अली, विजय सिंह, विजय प्रताप सिंह, विनोद चौरसिया, अखिलेश मिश्रा, मंगल गुप्ता, रामप्रकाश साहनी, अनुज अग्रवाल, डब्लू गुप्ता, अनूप कुमार, भगवान दास, राजेश कुमार, रामचंद्र सोनी, अजय जौहरी, बृजराज सोनी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

स्नेहा दुबे पंडित ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, वसई-विरार के विकास मुद्दों पर हुई चर्चा

मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा दुबे पंडित ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास नंदनवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं तथा लंबित जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वसई-विरार शहर के समग्र विकास के लिए आवश्यक विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। स्नेहा दुबे पंडित ने नागरिकों की समस्याओं, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई इस सकारात्मक चर्चा में नागरिक हितों को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेज करने तथा लंबित मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि वसई-विरार के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वह लगातार सरकारी स्तर पर फॉलो-अप करती रहेंगी, ताकि क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और शहर के विकास को नई गति मिल सके।

ट्रेन से गिर कर युवक घायल, जिला अस्पताल रेफर

निशानाथ

खेतासराय, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खेतासराय थाना क्षेत्र के शेखपुर मंसूर अली गांव में बुधवार की सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ग्रामीण रेलवे ट्रैक की तरफ शौच करने निकले थे तभी ट्रैक के पास घायल अवस्था में एक युवक को देखा और इसकी सूचना डायल 112को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकरअस्पताल पहुंचाया जहां इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी अयोध्या रेल प्रखण्ड पर गेट नंबर 52सी व 53सी के मध्य एक युवक आलोक दुबे पुत्र स्व0 राधेश्याम उम्र 25वर्ष निवासी ग्राम ककरापाल थाना अलीपुर जनपद अम्बेडकर नगर भोर में किसी ट्रेन से गिर गया था। ग्रामीणों ने देखा तो उसकी सूचना डायल 112पर दिया पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर पीएचसी सोंधी ले गए प्रथम उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां हालत सामान्य बताई जा रही है। युवक पुलिस भर्ती परीक्षा दे कर किसी ट्रेन से अपने घर वापस लौट रहा था। मामला भोर का होने की वजह से दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल सका। जिला अस्पताल में स्थित सामान्य बताई जा रही है। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं।

जीएसटी के नए फेरबदल से ठप हो सकता है सब्सक्रिप्शन वाला राइड-हेलिंग मॉडल

नई दिल्ली। एस्या (Esya) सेंटर ने आज अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है: 'बैलेंसिंग एफिशिएंसी एंड इक्विटी: एविडेंस फ्रॉम इंडियन टेक्नोलॉजी-इंटरमीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अंडर द जीएसटी(GST) रिजीम'। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी (GST) कानून की धारा 9(5) के तहत सब्सक्रिप्शन वाले राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी(GST) थोपना कानूनी रूप से उलझा हुआ और जमीनी स्तर पर लागू करना नामुमकिन है, जबकि इससे ड्राइवरों और आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। यह स्टडी 13 भारतीय शहरों के 1,044 ड्राइवरों और 1,059 यात्रियों से बातचीत पर आधारित है। यह आजकल तेजी से बढ़ रहे सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (SAAS) मॉडल की पड़ताल करती है, जो सिर्फ एक सिर्फ सवारी ढूंढ कर देने वाले माध्यम के रूप में काम करता है। इसमें ड्राइवर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए एक तय सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, लेकिन वे खुद किराया तय करते हैं, सीधे सवारी से पैसे लेते हैं और पूरी कमाई खुद रखते हैं। पुराने कमीशन-आधारित मॉडल के उलट, ये स्वाअर प्लेटफॉर्म न तो सफर का किराया तय करते हैं और न ही पैसों का लेनदेन संभालते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे सब्सक्रिप्शन मॉडल वाले प्लेटफॉर्म के किराए पर धारा 9(5) के तहत जीएसटी(GST) लगाना व्यावहारिक रूप से एक बड़ी चुनौती है।

इस मुद्दे पर बात करते हुए एस्या सेंटर की डायरेक्टर, मेघना बाल ने कहा भारत का मोबिलिटी सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। नए प्लेटफॉर्म मॉडल ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों को ज्यादा सहूलियत और विकल्प दे रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ईवाई (E) की टैक्स पार्टनर, जयश्री पार्थसारथी ने कहा डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के विकास ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नए जमाने के इन बिजनेस मॉडलों पर इनडायरेक्ट टैक्स (अप्रत्यक्ष कर) के नियमों को कैसे लागू किया जाए।

जौनपुर में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ, 5.40 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन-ए की खुराक

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देश पर बुधवार से जनपद में बाल स्वास्थ्य पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया गया। राजकीय लीलावती अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम ने 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाकर अभियान का उद्घाटन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह विशेष अभियान 10 जून से 9 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आयोजित टीकाकरण सत्रों में बच्चों को टीकाकरण के साथ-साथ विटामिन-ए की खुराक भी दी जाएगी।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नरेन्द्र सिंह ने बताया कि जनपद में 9 माह से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुल 5,40,601 बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विटामिन-ए की कमी से बच्चों में रतौंधी, अंधता, शारीरिक वृद्धि में कमी तथा विभिन्न संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है। ऐसे में यह अभियान बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि बाल स्वास्थ्य पोषण माह वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक छह माह के अंतराल पर बच्चों को विटामिन-ए की खुराक दी जाती है। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को कुल नौ खुराकें दी जाती हैं, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि बेहतर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम ने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को निर्धारित टीकाकरण सत्रों पर ले जाकर विटामिन-ए की खुराक अवश्य दिलाएं। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक सत्यव्रत त्रिपाठी, डीसीपीएम खुर्शेद रजा, एमएचसी नीरज सिंह, जिला समन्वयक गांधी सहित अस्पताल के चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, लाभार्थी बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

प्रतापगढ़ में शिक्षा का प्रकाश स्तंभ बना जेडी शिक्षा ग्राम, एजुकेशन फॉर ऑल का पैगाम

प्रतापगढ़। शिक्षा न केवल हमारे उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करती है, बल्कि समाज से अंधविश्वास और असमानता को मिटाकर एक मजबूत, प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखने में भी मदद करती हैं। यही कारण है कि हर समाज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। मुंबई के उद्योगपति और समाजसेवी दिनेश त्रिपाठी ने एजुकेशन फॉर ऑल की संकल्पना के साथ वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद स्थित कोहंडौर में राष्ट्रीय राजमार्ग के ठीक बगल जेडी शिक्षा ग्राम की स्थापना की। 43 एकड़ क्षेत्र में फैला यह शैक्षणिक संस्थान आज पूरी तरह से एजुकेशनल हब के रूप में तब्दील हो चुका है। फामेर्सी, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, लाइफ साइंस से लेकर आर्ट्स ,साइंस ,कॉमर्स, लॉ कॉलेज, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, लिबरल साइंस जैसे अनेक स्कूल और कॉलेज एक ही शैक्षणिक संस्थान ग्रुप के बैनर तले संचालित किया जा रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी के अनुसार भारत गांवों का देश है। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यही कारण है कि उन्होंने ग्रामीण शिक्षा को प्रभावशाली और गतिशील बनाने की दिशा में इसकी स्थापना की। उन्होंने कहा कि जेडी शिक्षा ग्राम विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि यहां अच्छे और प्रभावशाली शिक्षक रखे गए हैं। यहां पर इंडियाना मेडिसिना (आयुष) फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अकैडमी, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी, एग्रीकल्चर साइंस, सॉफ्ट स्किल्स, स्पिरिचुअल हीलिंग जैसे पाठ्यक्रमों के भी सुविधा है। 4000 से अधिक विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स के अलावा करीब डेढ़ सौ शिक्षक तथा 50 शिक्षणेत्तर कर्मचारी यहां कार्यरत हैं। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे ने 8 जून को जेडी शिक्षा ग्राम को करीब से जाकर देखा। यहां का वाचनालय, प्रयोगशालाएं देखने लायक है। दिनेश त्रिपाठी के सुपुत्र ज्योतिरादित्य त्रिपाठी अमेरिका के न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे हैं। इन दिनों वे छुट्टियों पर घर आए हुए हैं। उनसे भी कॉलेज के कार्यालय में मुलाकात हुई। शिक्षा को लेकर उनके युवा मन में भी ढेर सारे सपने दिखाई दिए। इस अवसर पर रमेश बहादुर सिंह (प्रशासनिक अधिकारी), डॉ एच. एस. चौरसिया (प्रिंसिपल, फॉमेर्सी कॉलेज), डॉ विपुल शुक्ल (प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज),डॉ जे. पी. एल. श्रीवास्तव (प्रिंसिपल, लॉ कॉलेज),

विनय त्रिपाठी (हेड, साइंस एंड आर्ट डिग्री कॉलेज) से भी मुलाकात हुई। कुल मिलाकर जेडी शिक्षा ग्राम शिक्षा के एक प्रकाश स्तंभ की तरह ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा है।

48 घंटे की मेहनत रंग लाई, बरेली पुलिस ने अगवा बच्चे को सकुशल कराया बरामद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के अपहरण किए गए एक मासूम बच्चे को बरेली पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की लगातार छापेमारी, तकनीकी जांच और कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया गया। बरामदगी के बाद भावुक दृश्य देखने को मिला, जब आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा ने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसका हौसला बढ़ाया। इस मानवीय पहल की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बच्चे की सुरक्षित बरामदगी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने लगातार 48 घंटे तक अभियान चलाकर आरोपियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। बच्चे के परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए राहत की सांस ली। इस सफल अभियान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुलिस की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और समर्पण से गंभीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। बरेली पुलिस की इस उपलब्धि की क्षेत्रभर में सराहना की जा रही है।

मामूली विवाद में युवक की मौत, भाई-भतीजा समेत कई घायल

-प्रियेश गुप्ता रुद्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बक्सा थाना क्षेत्र के सदुपुर गांव में बुधवार शाम मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका भाई, भतीजा समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 7 बजे किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि चार से पांच लोगों ने अजय सिंह (50) पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अजय सिंह को बचाने पहुंचे उनके छोटे भाई अखिलेश सिंह (55) और शिवम (25) भी हमले की चपेट में आ गए। मारपीट में अजय सिंह के पुत्र आकृत सिंह (17) गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अखिलेश सिंह के पुत्र हिमांशु सिंह को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने अजय सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल अखिलेश सिंह को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बक्सा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजय सिंह की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है।

एनजीटी सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने की पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा, जौनपुर के प्रयासों की सराहना

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के सदस्य/न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण संरक्षण कार्यों एवं एनजीटी के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों एवं नवाचारों का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया गया। समीक्षा के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, सीवेज प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट नियंत्रण, तालाबों एवं जलाशयों के संरक्षण, वृक्षारोपण तथा स्वच्छता अभियानों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। डॉ. अफरोज अहमद ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करते हुए जनपद जौनपुर में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही आमजन को जागरूक कर वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियानों को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. ने कहा कि एनजीटी सदस्य द्वारा दिए गए सभी सुझावों एवं निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। बैठक के उपरांत डॉ. अफरोज अहमद ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) प्रोमिला सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की, 25 जून तक सामुदायिक शौचालय क्रियाशील करने के निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं संचालन की समीक्षा करते हुए सभी एडीओ पंचायतों को निर्देशित किया कि 25 जून तक सभी सामुदायिक शौचालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) के निर्माण एवं संचालन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर भूमि विवाद अथवा अन्य तकनीकी कारणों से कार्य प्रभावित हो रहा है, वहां संबंधित विभागों के समन्वय से समस्याओं का समाधान कर कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए।

अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने शासन के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों के शिलापट्ट अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना एवं उपयोगिता की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कराने पर बल दिया।

जिलाधिकारी ने डिजिटल विलेज की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट को नियमित रूप से संचालित रखने तथा उसकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन सिंह ने आश्वस्त किया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जांच में खुलासा: पार्क निर्माण से नहीं, गड्ढे में फिसलकर डूबने से हुई थी वृद्ध की मौत

शाहगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। दैनिक समाचार पत्र में 9 जून 2026 को प्रकाशित ₹पार्क के नाम पर खोदे गए गड्ढे में सिर के बल गिरने से वृद्ध की मौत, सदमे में बड़े भाई की जान गई₹ शीर्षक समाचार के संबंध में उप जिलाधिकारी शाहगंज द्वारा कराई गई जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। उप जिलाधिकारी के अनुसार स्थलीय निरीक्षण एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान मृतक के दामाद, बड़े भाई तथा पत्नी उपस्थित रहे। जांच में पाया गया कि ग्राम परासिन, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज निवासी स्वर्गीय रामनारायण पुत्र सियम्बर की मृत्यु पार्क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतक के आवास के उत्तर दिशा में सड़क से सटी गाटा संख्या 939 की भूमि स्थित है, जो बाबा रघुवर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के रूप में दर्ज है। इसी भूमि पर एक छोटा गड्ढा बना हुआ है, जहां आसपास के घरों और मृतक के घर का पानी नाली के माध्यम से वर्षभर एकत्रित होता रहता है। बताया गया कि लगभग 70 वर्षीय रामनारायण अक्सर उक्त स्थान और आसपास की खाली भूमि पर जाया करते थे। अत्यधिक आयु के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर सिर के बल गड्ढे में गिर गए, जिससे डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण डूबना ही प्रमाणित हुआ है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि मृतक के चचेरे भाई रामदवर लंबे समय से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे और 7 जून को उनकी तबीयत अत्यधिक खराब थी। इसी कारण परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदार उनकी कुशलक्षेम जानने गए हुए थे। इसी दौरान रामनारायण नित्यक्रिया के लिए बाहर गए और दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना के समय घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था।

मृतक के दामाद फुलचंद ने भी जांच के दौरान बताया कि रामनारायण को कभी-कभी चक्कर आने की समस्या रहती थी। उन्होंने कहा कि समाचार में प्रकाशित तथ्यों की पुष्टि जांच में नहीं हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि मौके पर पार्क निर्माण का कोई कार्य नहीं चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक के भाई की मृत्यु किसी सदमे के कारण नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही ब्लड कैंसर की बीमारी के कारण स्वाभाविक रूप से हुई थी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि प्रकरण को दैवीय आपदा की श्रेणी में मानते हुए नियमानुसार चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मृतक की पत्नी श्रीमती सिरमा देवी को प्रदान किए जाने के लिए पत्रावली स्वीकृत कर दी गई है। यह खबर प्रशासनिक जांच रिपोर्ट पर आधारित है और प्रकाशित समाचार में सामने आए तथ्यों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है।

रील गैंग, रास्ता और जमीन विवाद में 7 गिरफ्तार

खेतासराय,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खेतासराय थाना पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई में सात लोगों को शांति भंग की आशंका के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर रील पोस्ट करने, रास्ते के विवाद तथा जमीन संबंधी विवाद को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना थी। पुलिस ने ग्राम सोंगर निवासी मुखई राम पुत्र स्व. राम निरंजन एवं पंकज चौहान पुत्र पतिराम चौहान, ग्राम खलौतीपुर निवासी सर्वेश कुमार पुत्र रामराज, ग्राम बहादुरपुर निवासी अजय कुमार पुत्र कमला प्रसाद, तथा ग्राम नदौली निवासी शिवमूरत यादव पुत्र रामअवध, विनोद पुत्र शिवमूरत यादव और रणजीत यादव पुत्र राममूरत यादव को गिरफ्तार किया। सभी आरोपितों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई।

वात्सल्य शिरोमणि दादी माँ रतनबाईजी के 85वें जन्मोत्सव पर जीवंत जीवन गौरव महा महोत्सव सम्पन्न

उदयपुर (उत्तरशक्ति)। झाड़ोल-सराड़ा में वात्सल्य शिरोमणि श्रद्धेय श्रीमती रतनबाईजी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री रंगलाल जी पटवारी झगड़ावत के 85वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर उनके परिवारजनों द्वारा भव्य ₹जीवंत जीवन गौरव महा महोत्सव₹ का आयोजन किया गया। आयोजन में अपुर्व आशीर्वाद स्वर्गीय रंगलाल जी पटवारी साहेब, स्वर्गीय ईश्वरलालजी, स्वर्गीय निर्मलाबाई, स्वर्गीय हरीश कुमार झगड़ावत का रहा एवं परम सानिध्य श्रीमती कांता देवी,पौत्र राहुल कुमार हिनादेवी, कपिल कुमार,हेमादेवी एवं रवि कुमार झगड़ावत की विशेष सहभागिता से संपन्न हुआ।

समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के मुख्य संयोजक प्रमोद सामर, विशिष्ट अतिथि सकल दिगम्बर जैन त्रिवेणी संगम समाज झाड़ोल के अध्यक्ष केशूलाल मालवी, कोहिनूर अतिथि धनराज सकावत तथा देहात चित्तौड़ा जैन समाज अध्यक्ष राजेश परतियोत की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ।

इस अवसर पर मल्लिनाथ स्वामी जिनालय, झाड़ोल में रजत कलश अर्पित किया गया। तत्पश्चात समाज के पंचों एवं गणमान्यजनों द्वारा श्रद्धेय श्रीमती रतनबाईजी का बहुमान कर उन्हें जीवंत जीवन गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सर्वाधिक भावनात्मक एवं प्रेरणादायी क्षण वह रहा जब ममता, त्याग, सेवा और वात्सल्य की महासागर पूज्यनीय मातो रतनबाईजी के अग्रज जमाई राजमल लीलादेवी पेमावत, राजमल कांता देवी करमावत, गिरीश कुमार सुशीला देवी पटवा, हितेश जी बरखा देवी अदवासीया ने जीवन गौरव स्वर्ण वात्सल्य सम्मान अलंकरण-पत्र समर्पित किया गया। इस विहंगम अवसर पर उपस्थित अनेक जनों की आंखें भावुक हो उठीं। कार्यक्रम के अंतर्गत तीर्थराज सम्मेद शिखर की महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। यह आयोजन श्रीमती रतनबाईजी की चिरकालीन अभिलाषा एवं मनोकामना को साकार रूप प्रदान करने वाला भावनात्मक एवं प्रेरणादायी अवसर बना। समारोह में चितौड़ा समाज के 15 गांवों के प्रमुख सेठ, समाजबंधु, पंच एवं गणमान्यजन, शुभचिंतकों की गरीमामय उपस्थित रही। समस्त सम्माननीय महानुभावों ने श्रीमती रतनबाईजी के स्वस्थ, सुखमय एवं दीघार्यु जीवन की मंगलकामनाएं व्यक्त करते हुए आयोजन को मातृभक्ति, सेवा, संस्कार एवं पारिवारिक मूल्यों का अनुपम उदाहरण बताया। यह जानकारी पत्रकार राजमल पेमावत द्वारा प्रदान की गई।